Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-24 16-31 दिसंबर, 2024 (पाक्षिक) ₹20

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाया गया है'

शपथ ग्रहण समारोह, महाराष्ट्र

'महायुति सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी'

जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है?

मुंबई (महाराष्ट्र) में 05 दिसंबर, 2024 को महायुति सरकार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री देवेन्द्र फडणवीस को बधाई देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस पर शपथ लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण

संसद पुस्तकालय (नई दिल्ली) में 02 दिसंबर, 2024 को 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ली तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

एक गरिमामय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में महायुति के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ने 05 दिसंबर, 2024 को...

11 'संविधान दिवस' की 75वीं वर्षगांठ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया...

13 भाजपा केंद्रीय कार्यालय में 'संविधान दिवस समारोह'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 नवंबर, 2024 को केंद्रीय कार्यालय...

14 जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस का संबंधः 'भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय'

संसद में कांग्रेस एवं विपक्षी नेताओं की नारेबाजी तथा व्यवधान के बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रकाश...

25 रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया-फर्स्ट' नीति और 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की

राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री...

लेख

टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत का बेहतर प्रदर्शन / **जगत प्रकाश नड्डा** 26

'सहकार से समृद्धि' का भारतीय दर्शन / **अमित शाह** 28

महाराष्ट्र का संदेश / **शिव प्रकाश** 30

मन की बात

2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैंः नरेन्द्र मोदी 32

अन्य

देवेंद्र फडणवीस चुने गए महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता 10

'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' 12

भारत में डिजिटल भुगतान में एक क्रांति- एक रिपोर्ट 17

पिछले पांच वर्षों में 60 जिले वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से हुए मुक्त 19

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2024 तक 43,30,121 खाते खोले गए 19

कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ओएनओएस) को दी मंजूरी 21

शून्य मामलाः भारत की पोलियो उन्मूलन महागाथा 22

मोदी स्टोरी 24

कमल पुष्प 24

डॉ. अम्बेडकर के 'महापरिनिर्वाण दिवस' पर कार्यक्रम आयोजित 33

पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान देंः नरेन्द्र मोदी 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

बीते 10 वर्षों में नॉर्थ-ईस्ट के युवाओं ने स्थायी शांति के हमारे प्रयासों में जिस प्रकार बढ़-चढ़कर भागीदारी की है, उससे इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है।

(06 दिसंबर, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो लता की तरह किसी पेड़ से चिपक जाती है और खुद खड़े होकर पेड़ को खत्म कर देती है।

(07 दिसंबर, 2024)

अमित शाह

नए आपराधिक कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारतवासियों को न्याय दिलाना है।

(03 दिसंबर, 2024)

राजनाथ सिंह

महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। उनके विचार एवं दृष्टिकोण भारत को प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान के लिए उनका ऋणी रहेगा। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि!

(06 दिसंबर, 2024)

बी.एल. संतोष

श्री देवेन्द्र फडणवीस, श्री एकनाथ शिंदे, श्री अजित पवार को आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई! यह प्रदेश के लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा।

(5 दिसंबर, 2024)

नितिन गडकरी

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-752जी के सेंधवा से खेतिया (मप्र-महाराष्ट्र सीमा) खंड को 615.61 करोड़ रुपये की लागत से पक्की सड़क के साथ 2-लेन में बदलने और पुनर्वास को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच अंतर-राज्यीय संपर्क में सुधार करना है। यह सड़क सीधे आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जुड़ी हुई है, जिससे निवाड़ी, पानसेमल और खेतिया से इंदौर शहर (मप्र) तक आवाजाही में सुधार होगा। बड़वानी जिले के सेंधवा, निवाली, पानसेमल और खेतिया से गुजरने वाली परियोजना सड़क क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

(6 दिसंबर, 2024)

'कमल संदेश' परिवार

की ओर से

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी

को उनकी जयंती (25 दिसंबर) पर

शत शत नमन!

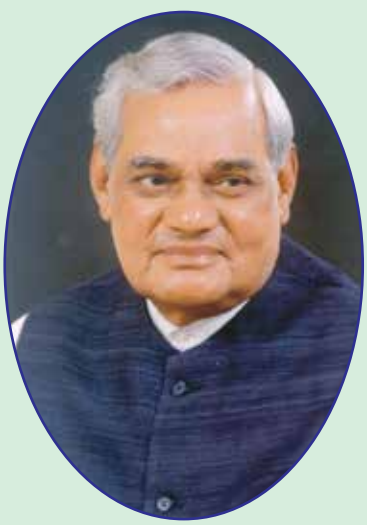

संपादकीय

बेनकाब हुआ कांग्रेस-सोरोस गठबंधन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में श्री देवेन्द्र फडनवीस, उपमुख्यमंत्री के रूप में श्री एकनाथ शिंदे एवं श्री अजित पवार के शपथ लेने के साथ ही 'विकसित भारत' का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हुआ है। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि 'डबल इंजन' की सरकार प्रदेश को नई ऊंचाइयां देगी। महायुति पर अथाह आशीर्वाद बरसाकर लोगों ने यह दिखा दिया है कि एकजुटता से विकास एवं सुशासन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'एक हैं तो सेफ हैं' के आह्वान से जनता में अद्भुत एकजुटता आई, जिन्होंने एकमत से परफॉर्मेंस की राजनीति एवं 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए मतदान किया। महाराष्ट्र की जनता की एकजुटता महायुति के महाविजय में परिणत हुई तथा पिछले 50 वर्षों के सभी रिकार्डों को तोड़ते हुए एक मजबूत, समृद्ध एवं सुरक्षित महाराष्ट्र का पथ प्रशस्त हुआ।

फ्रांस की मीडिया समूह 'मीडियापार्ट' द्वारा 02 दिसंबर, 2024 को आर्गनाईज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के संबंध में जारी खोजी रिपोर्ट से कांग्रेस-ओसीसीआरपी के बीच के संबंध उजागर हुए हैं। यह सच्चाई अब छुपी नहीं है कि ओसीसीआरपी भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा पर हमले करके भारत सरकार को अस्थिर करने का कुचक्र रच रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस संबंध पर प्रश्न खड़े करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया-पेसिफिक (एफडीएल-एपी) के सह-अध्यक्ष पद स्वीकार करने पर भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। ध्यातव्य है कि यह फोरम कश्मीर को 'स्वतंत्र इकाई' मानती है तथा पाकिस्तान समर्थक मानी जाती है। साथ ही, ओसीसीआरपी एवं एफडीएल-एपी, दोनों को विवादास्पद अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से धन प्राप्त होता है। जॉर्ज सोरोस कई बार भारत सरकार को अस्थिर करने, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के प्रयासों के कारण विवादों में रहे हैं। ओसीसीआरपी भारत में कई मीडिया समूहों को भारत सरकार, इसके उद्योगपतियों एवं भारतीय हितों के विरुद्ध आलोचनात्मक लेख लिखवाएं हैं। इन्हीं लेखों को विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने बार-बार उद्धृत कर भारत के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने के प्रयास किये हैं। जब-जब राहुल गांधी ने इन आधारहीन रिपोर्टों को उद्धृत किया है, विवादास्पद व्यक्तियों से मिले हैं, भारत विरोधियों को गले लगाया है तथा विदेशों में भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिए हैं, उनका इन समूहों के साथ का संबंध बेनकाब हुआ है। ये विवादास्पद समूह कई देशों में सरकारों को अस्थिर करने का व उनकी संप्रभुता पर आघात करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे विवादित समूहों के रिपोर्ट, जो लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं, उसको उद्धृत करना यह दिखाता है कि श्री राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने के भयावह षड्यंत्र में उनका साथ दे रहे हैं तथा 'विकसित भारत' के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस को इन भारत-विरोधी समूहों, जो निरंतर भारत पर हमले करते हैं तथा राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सुरक्षा पर आघात करते हैं, उनके साथ अपने संबंधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'एक हैं तो सेफ हैं' के आह्वान से जनता में अद्भुत एकजुटता आई, जिन्होंने एकमत से परफॉर्मेंस की राजनीति एवं 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए मतदान किया

आज जब पूरा देश संविधान के अंगीकार होने का 75वां वर्ष मना रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को 26 नवंबर, 2024 को संविधान की गौरवमयी यात्रा पर संबोधन के साथ ही वर्षभर का उत्सव प्रारंभ हो गया। ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान को देश ने 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया था, परंतु इस दिन को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जन-जन में संविधान के मूल्यों तथा 'भारत रत्न' बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा संविधान निर्माताओं के योगदानों से परिचित कराना भी है। आज जब देश विकसित होने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ चला है, भारत का संविधान सर्वसमावेशी एवं सामाजिक न्याय, समता एवं बंधुत्व के आधार पर एक न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ली तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ

एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

एक गरिमामय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में महायुति के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ने 05 दिसंबर, 2024 को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री फड़णवीस, जो नागपुर दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, 04 दिसंबर को मुंबई में आयोजित एक बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए। उन्होंने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री फड़णवीस के साथ शिवसेना प्रमुख श्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता श्री अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र सरिता गंगाधरराव फड़णवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल ने श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे और श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुंबई के आजाद मैदान में संपन्न इस शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति, व्यापार, खेल एवं सिने जगत के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को हुए चुनाव में महायुति ने शानदार विजय प्राप्त करते हुए 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं। भाजपा 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो अब तक की उसकी सबसे बड़ी संख्या है, जबकि शिव सेना एवं राकांपा को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिलीं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री एस. जयशंकर, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री भूपेन्द्र यादव एवं श्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे।

एनडीए के नेताओं— केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान (लोक

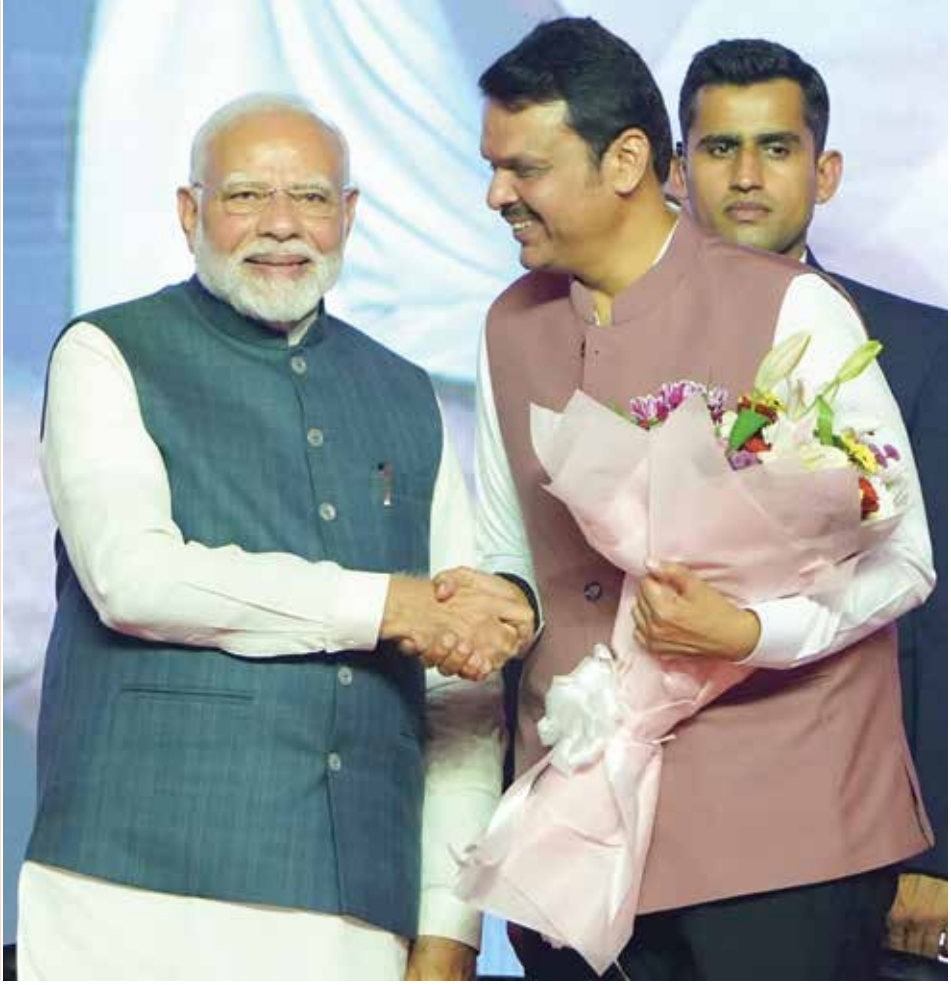

जनशक्ति पार्टी-रामविलास), श्री जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा-सेक्युलर), श्री रामदास अठावले (आरपीआई-ए) और श्री प्रतापराव जाधव (शिवसेना) भी उपस्थित थे।

समारोह में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण— योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), श्री पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड), श्री नायब सिंह सैनी (हरियाणा), श्री भूपेन्द्र पटेल (गुजरात), श्री प्रमोद सावंत (गोवा), श्री हिमंत बिस्वा सरमा (असम), श्री विष्णु देव साय (छत्तीसगढ़), श्री भजनलाल शर्मा (राजस्थान), श्री मोहन चरण माझी (ओडिशा), श्री पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश), श्री एन. बीरेन सिंह (मणिपुर) एवं श्री माणिक साहा (त्रिपुरा) शामिल हुए।

एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण— श्री नीतीश कुमार (बिहार), श्री कॉनराड संगमा (मेघालय), श्री नेफ्यू रियो (नागालैंड), श्री प्रेम सिंह

श्री देवेन्द्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई।

श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजित पवार जी को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई।

यह टीम अनुभव और उत्साह का मिश्रण है और इसी टीम के सामूहिक प्रयासों के कारण महायुति को महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जनादेश मिला है। यह टीम राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मैं महाराष्ट्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री देवेन्द्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे एवं श्री अजित पवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

महाराष्ट्र की जनता-जनार्दन ने भाजपा और महायुति को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान कर डबल इंजन सरकार की विकासवादी नीतियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद प्रदान किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार प्रदेश के विकास को तीव्र गति प्रदान करने के साथ 'विकसित महाराष्ट्र' के हमारी परिकल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करेगी।

- जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्री देवेंद्र फडणवीस का जीवन परिचय

- श्री देवेन्द्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस (देवेंद्र फडणवीस) का जन्म 22 जुलाई, 1970 को नागपुर, महाराष्ट्र में श्री गंगाधर फडणवीस एवं श्रीमती सरिता फडणवीस के घर हुआ था।
- उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1992 में एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री ली और जर्मनी के बर्लिन के फ्री यूनिवर्सिटी से मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी हासिल किया, जो वर्ष 1998 में पूर्ण हुआ।
- श्री फडणवीस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नब्बे के दशक के मध्य में की थी। एक कॉलेज छात्र के रूप में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के सक्रिय सदस्य बने।
- वर्ष 1992 में 22 वर्ष की आयु में वह पार्षद बने। इसके 5 वर्ष बाद वह साल 1997 में 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने।
- श्री फडणवीस ने प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1999 में कदम रखा, जब वह विधानसभा के लिए चुने गए।
- 1999 से श्री फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- वह 11 अप्रैल, 2013 से 6 जनवरी, 2015 तक महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रहे।
- श्री फडणवीस पहली बार 2014-2019 तक पांच साल की अवधि के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वह 44 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के इतिहास में वह दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे।
- मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल 23 नवंबर, 2019 को आरंभ हुआ; हालांकि, यह सरकार कुछ ही दिनों तक चली।

- 30 जून, 2022 को श्री फडणवीस ने महाराष्ट्र के 9वें उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने।
- 23 नवंबर, 2024 को विधानसभा चुनावों में एक भव्य जीत के बाद श्री देवेंद्र फडणवीस को 04 दिसंबर, 2024 को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया।
- उन्होंने 05 दिसंबर, 2024 को मुंबई में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

तमांग (सिक्किम) और श्री एन. रंगास्वामी (पुडुचेरी) भी उपस्थित थे। एनडीए शासित आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण भी इस समारोह में शामिल हुए।

उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी, श्री नोएल टाटा, श्री कुमारमंगलम बिड़ला एवं सिने जगत से श्री शाहरुख खान, श्री सलमान खान, श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने, श्री संजय दत्त एवं सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी श्री सचिन तेंदुलकर शामिल हुए। इस अवसर पर कई देशों के राजनयिक भी मौजूद थे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई! वह अपने साथ नए महाराष्ट्र के लिए एक जीवंत दृष्टिकोण एवं समृद्ध प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं।

मुझे विश्वास है कि वह महाराष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनके कार्यकाल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं श्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भी बधाई देता हूं! प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री एकनाथ शिंदे जी व श्री अजित पवार जी को हार्दिक बधाई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महायुति ने प्रदेश में संस्कृति के सम्मान और महिलाओं, वंचितों के साथ-साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस समर्पण भाव से कार्य किया है, वह आप तीनों के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। महायुति के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास और विरासत के संगम का केंद्र बनकर देश का नंबर 1 राज्य बनेगा।

- अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

शपथ लेने के बाद श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं महाराष्ट्र के सामने सिर झुकाता हूं। महाराष्ट्र के आशीर्वाद से मुंबई के आज़ाद मैदान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।"

श्री फड़णवीस ने कहा कि हम अगले पांच वर्षों में एक स्थिर सरकार प्रदान करेंगे और महायुति सरकार में राज्य में बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति होगी। उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री फड़णवीस को हर संभव सहयोग दूंगा और एक टीम के रूप में काम करूंगा।"

इसके पश्चात्, मुंबई में मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री फड़णवीस एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ मासाहेब, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना को नमन किया। ■

देवेंद्र फडणवीस चुने गए महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने 04 दिसंबर, 2024 को मुंबई में सर्वसम्मति से श्री देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना। इस निर्णय की घोषणा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने की।

श्री रूपाणी ने बैठक में कहा, "कोई अन्य प्रस्ताव नहीं आया, इसलिए श्री फड़णवीस के निर्विरोध नेता चुने जाने की घोषणा की गई।"

विधायक दल की बैठक के दौरान महाराष्ट्र भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटिल ने नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और विधान परिषद् सदस्य श्रीमती पंकजा मुंडे ने इसका समर्थन किया।

पार्टी के एक अन्य केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर महाराष्ट्र जनादेश के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "यह विकासशील भारत के लिए एक जनादेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'डबल इंजन' सरकार महाराष्ट्र को पूरे उत्साह के साथ विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। घोषणापत्र में किये गये वादे पूरे किये जायेंगे।"

भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति के तीनों नेता— श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। ■

'संविधान दिवस' की 75वीं वर्षगांठ

हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का 75 वर्ष पूरा होना अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने इस अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और संविधान की सराहना की।

भारतीय संविधान के संदर्भ में संविधान सभा की विस्तृत बहस और चर्चाओं को याद करते हुए श्री मोदी ने बाबासाहेब अंबेडकर को उद्धृत करते हुए कहा, "संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह एक भावना है, यह हमेशा युग की भावना है।"

पहली बार जम्मू-कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया

श्री मोदी ने कहा, "हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है।" उन्होंने आगे कहा कि संविधान ने पिछले 75 वर्षों में सामने आई विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सही रास्ता दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान ने भारतीय लोकतंत्र के सामने आए आपातकाल के खतरनाक समय का भी सामना किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान ने देश की हर जरूरत और उम्मीद को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दी गई शक्ति के कारण ही डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान आज जम्मू-कश्मीर में भी लागू है। श्री मोदी ने आगे कहा कि आज पहली बार जम्मू-कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हमें मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में सही रास्ता दिखा रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि अब भारत के भविष्य का मार्ग बड़े सपनों और बड़े संकल्पों को हासिल करने से जुड़ा है, श्री मोदी ने उल्लेख किया कि आज प्रत्येक नागरिक का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण करना है।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत का मतलब है एक ऐसा स्थान, जहां प्रत्येक नागरिक को जीवन की गुणवत्ता और सम्मान मिले। श्री मोदी ने कहा कि यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम है और यही संविधान की भावना भी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे पिछले दशक में लोगों के 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलना, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी।

पिछले दशक में चार करोड़ लोगों को पक्के घर सुनिश्चित किए गए

श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में चार करोड़ लोगों को पक्के घर सुनिश्चित किए गए, 10 करोड़ घरेलू महिलाओं को गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए गए। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में केवल 3 करोड़ घर ऐसे थे, जिनमें घरेलू नल की सुविधा थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक घरेलू नल जल कनेक्शन दिए हैं, जिससे नागरिकों और विशेष रूप

से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे संविधान की भावना मजबूत हुई है।

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के इन प्रतीकों को संविधान में जगह दी गई, ताकि सुनिश्चित हो सके कि यह हमें मानवीय मूल्यों के प्रति निरंतर जागरूक और सचेत रखे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता लागू की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल गई है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है, जिसने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया है और भारत ही ऐसा देश है, जिसने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से आज बच्चों के बीच टीकाकरण कवरेज 100% के करीब पहुंच गया है, जबकि पहले यह 60% से भी कम था।

सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 100 से अधिक सबसे पिछड़े जिलों को चुना गया है और हर विकास मानक के लिए गति बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है।

उन्होंने आगे कहा कि पानी के अन्दर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के माध्यम से अब अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने घरों और कृषि भूमि के भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में विकसित देशों से बढ़त हासिल की है।

श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए आधुनिक अवसंरचना का तेजी से विकास एक बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से पैसे की बचत होती है और साथ ही परियोजना की उपयोगिता भी सुनिश्चित होती है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति मंच का उपयोग करके अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है और 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया गया।

संबोधन का समापन करते हुए श्री मोदी ने 26 नवंबर, 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भाषण की पंक्तियों को उद्धृत किया और कहा, "आज भारत को जरूरत है, केवल ईमानदार लोगों के एक समूह की, जो राष्ट्र के हितों को अपने हितों से आगे रखें।" उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की यह भावना आने वाली सदियों तक भारत के संविधान को जीवित रखेगी। ■

'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान'

भारत ने 26 नवंबर, 2024 का दिन संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। 26 नवंबर, 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू किया गया, जिससे भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। 2015 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन राष्ट्र संविधान को अंगीकृत किए जाने का जश्न मनाता है।

75 वर्ष का स्मारक समारोह वर्ष भर चलेगा और गतिविधियां चार स्तंभों पर केंद्रित होंगी— अर्थात संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का उत्सव। स्मरणोत्सव कार्यक्रमों का मुख्य समारोह 26 नवंबर, 2024 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस 2024 के समारोह में शामिल हुए।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि हमारा संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बदलते समय की आवश्यकता अनुरूप नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था बनाई थी। हमने संविधान द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से जुड़े कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए हैं। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया गया है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 नवंबर, 2024 को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित 'संविधान दिवस समारोह' के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं श्री दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं श्री वीरेंद्र कुमार, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री नड्डा ने सभागार में उपस्थित सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई।

देश को आगे बढ़ाने में संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

श्री नड्डा ने कहा कि आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देश के समक्ष रखा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ है। देश को आगे बढ़ाने में संविधान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को एकरूपता प्रदान की। संविधान सभा में हुई चर्चाओं और बहसों की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने संविधान के रूप में देश को सबसे बड़ा उपहार प्रदान किया। संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस देश के नेतृत्व को संविधान दिवस मनाने में 65 साल लग गए, यह देश के नेतृत्व पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत की और 26 नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस को याद किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की। देश की आजादी की बात करने वाले और इतने वर्षों तक देश पर राज करने वाले लोगों की संविधान के प्रति सोच और प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं। 2015 में जब संसद में संविधान दिवस मनाने का मुद्दा उठा तो कांग्रेस ने कहा कि जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है? लेकिन दो दिनों की चर्चा और बहस के बाद देश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को उसके वास्तविक स्वरूप में देश के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठा भी संविधान की प्रस्तावना को दोहराती है जो लिंग, जाति और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करती है तथा अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया गया है। संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'प्रकृति में एकात्मक एवं संरचना में संघीय' (unitary in nature, federal in structure) है तथा भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को माना एवं राज्यों को उचित गति से आगे बढ़ाने का काम किया है।

भाजपा-एनडीए सरकार ने संविधान की आत्मा को लागू करने में सफलता पाई है

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-एनडीए की सरकार ने संविधान की आत्मा को पूर्ण रूप से लागू करने में सफलता पाई है। जहां संविधान सभी राज्यों को समान मानता था, वहीं जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A जैसे प्रावधान वर्षों से लागू थे। 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुरूप अन्य राज्यों की तरह समान अधिकार दिया गया। महिला आरक्षण विधेयक, जो पहली बार 1996 में लोकसभा में पेश हुआ था और वर्षों तक बिना किसी निर्णय के अटका रहा, लेकिन मोदी सरकार 2.0 ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करके महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। इसी तरह, ओबीसी के लिए न्याय और संविधान की रक्षा की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया, जो समाज में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या संबंध है: जगत प्रकाश नड्डा

संसद में कांग्रेस एवं विपक्षी नेताओं की नारेबाजी तथा व्यवधान के बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 दिसंबर, 2024 को जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के भारत विरोधी रुख पर गंभीर सवाल उठाये और उनके संगठनों के साथ संबंध रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। इस दौरान श्री नड्डा ने 'जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच संबंधों' पर स्पष्टीकरण देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के श्री सोरोस द्वारा वित्तपोषित संगठनों के साथ संबंध हैं और गांधी परिवार भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ओसीसीआरपी (संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना) जैसे समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है। श्री नड्डा ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी के एफडीएल-एपी के साथ संबंध रहे हैं, जिसने कश्मीर को एक 'स्वतंत्र राष्ट्र' बनाने के विचार का समर्थन किया है, इस संस्था को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से धन मिल रहा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा 'संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) उन संगठनों में से एक है, जिनके माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने सदन में उन सभी मुद्दों को उठाया है, जिन्हें ओसीसीआरपी ने उठाया था। विपक्षी नेता देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध हैं'?

कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खेल रही है

भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही विपक्षी पार्टी एवं सोरोस के संबंधों का जिक्र करते हुए श्री नड्डा ने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के हथियार के रूप में काम करने की बात कही। उन्होंने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी फोरम ऑफ द् डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष हैं, जिसे सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। "यह संबंध चिंता का विषय है...'। 'इससे भारत की छवि खराब हो रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है। लोग चिंतित हैं... कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खेल रही है। इसलिए, हम चर्चा चाहते हैं।"

ओसीसीआरपी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अस्थिर करने के लिए प्रयासरत

श्री नड्डा ने कहा, "संगठित अपराध एवं भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अस्थिर करने के लिए प्रयासरत है। ओसीसीआरपी ने जो कुछ भी रिपोर्ट किया है, उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा संसद में उठाया है और साबित किया है कि वह बाहरी ताकतों का हथियार बन गये हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे देश में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं।"

देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरनाक

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक के सह-अध्यक्ष हैं। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को एक अलग इकाई मानता है। कांग्रेस ऐसे संगठनों के साथ मिली हुई है, जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। यह देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इस तरह की गतिविधि के लिए जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडिंग की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एवं जॉर्ज सोरोस के बीच क्या संबंध है?

श्री नड्डा ने कहा कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन वह हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम देश के लिए खड़े हैं। मैं उनसे वादा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो लोग अभी भी विदेशी प्रभाव में आकर भारत में बदलाव लाने का सपना देख रहे हैं, वह सफल नहीं होंगे।

भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास

इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी सोनिया गांधी एवं जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है।

क्या सोरोस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे दिए?

भाजपा सांसद श्री निशिकांत दुबे ने 06 दिसंबर को कहा, "कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के साथ मिली हुई है, क्या सोरोस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे दिए या नहीं? सोरोस ने 1000 भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पैसे दिए और उनमें से कितने कांग्रेस नेताओं के बच्चे हैं?'

क्या कांग्रेस उत्तर दे सकती है?

- ऐसा क्यों होता है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक उससे पहले विदेश से कोई न कोई मुद्दा उठाया जाता है और कांग्रेस उसी मुद्दे पर संसद को बाधित करने लग जाती है? क्या यह महज एक संयोग है या फिर व्यवस्थित रूप से भारत विरोधी प्रयोग है?
- मीडिया में विषय आया है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक (FDL-AP) जिसके के प्लेटफ़ॉर्म से जिस तरह की भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित बातें कही जा रही हैं, उसमें सोनिया गांधी जी सह-अध्यक्ष हैं और भारत विरोधी एजेंडा के सूत्रधार जॉर्ज सोरोस इसे फंड कर रहे हैं।
- भाजपा कांग्रेस और विपक्ष से स्पष्ट रूप से पूछना चाहती है कि FDL-AP से कांग्रेस के और सोनिया गांधी जी के क्या संबंध हैं? सोनिया गांधी ने इस संस्था में सह-अध्यक्ष का पद क्यों स्वीकार किया था?
- FDL-AP के प्लेटफ़ॉर्म से जिस तरह जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में बातें की जा रही हैं, क्या इसमें सह-अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी जी की सहमति है?
- भाजपा का स्पष्ट रूप से मानना है कि जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े संगठन भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह साजिश देशद्रोह के समकक्ष है। यदि कांग्रेस का ऐसे लोगों के साथ संबंध है तो कांग्रेस यह बताए कि क्या उनका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है?
- देशद्रोही शक्तियों के साथ कांग्रेस के लोग पदाधिकारी बने बैठे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं, मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, उनके साथ कांग्रेस की दोस्ती का राज क्या है?
- अफसोस की बात ये है कि देश के ऊपर जो रहस्यपूर्ण प्रश्न बाहर से उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस उनका साथ दे रही है। उनका साथ देना एक प्रकार से देशद्रोही शक्तियों के साथ हाथ मिलाने के समान है।
- विदेशी शक्तियों के साथ खड़े रहने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। यह वही कांग्रेस है जिसने तेल के बदले कूपन लिए थे और सद्दाम हुसैन से पैसा लिया था जिसका 2005 की वोल्कर रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ था।
- कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विदेश मंत्री ने खुद अपनी किताब में सोनिया गांधी को लिखे पत्र में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार किया था।
- राजीव गांधी फाउंडेशन को भी सोरोस की संस्था से पैसे मिले थे, जिसकी खबरें मीडिया में पहले से हैं।

भाजपा जानना चाहती है कि सोनिया गांधी का एफडीएल-एपी से क्या संबंध है

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 09 दिसंबर, 2024 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कथित सांठगांठ एवं भारतीय संसद के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि यह पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, तो कुछ विदेशी रिपोर्ट या घटनाएं घटित होती हैं, जिससे संसद की कार्यवाही बाधित होती है।

- उदाहरण के तौर पर किसानों से संबंधित रिपोर्ट 3 फरवरी, 2021 को आई थी, जबकि भारतीय संसद का सत्र 29 जनवरी, 2021 को था।
- पेगासस रिपोर्ट 18 जुलाई, 2021 को आई, जबकि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई, 2021 को था।
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट 24 जनवरी, 2023 को आई, जब संसद का बजट सत्र 30 जनवरी, 2023 को था।
- बीबीसी की डाक्यूमेंट्री 17 जनवरी, 2023 को आई, जबकि संसद का सत्र 30 जनवरी, 2023 से शुरू हुआ था।
- मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई, 2023 को रिलीज हुआ, जबकि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई ,2023 को शुरू हुआ।
- 10 मई, 2024 को वैक्सीन से संबंधित रिपोर्ट आई, जबकि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे।
- अगस्त, 2024 में सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट आई और हाल ही में 25 नवंबर से भारत का संसद सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन 20 नवंबर को यूएस में एक रिपोर्ट जारी हो गई।

डॉ. त्रिवेदी ने पूछा, "क्या यह महज संयोग है या कोई सुनियोजित भारत विरोधी प्रयोग है?" उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष एवं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से पूछना चाहती है और उनसे जवाब की अपेक्षा करती है –

- कांग्रेस एवं सोनिया गांधी का FDL-AP से क्या संबंध है? FDL-AP के मंच से जिस तरह से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, क्या यह कांग्रेस की सहमति से हो रहा है?
- कांग्रेस के लोग देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि वह भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उनसे कांग्रेस का क्या संबंध है?

जॉर्ज सोरॉस और राहुल गांधी एक ही विचारधारा के दो चेहरे हैं

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने 05 दिसंबर, 2024 को भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में एक प्रेस वार्ता में फ्रेंच अखबार 'मीडिया-पार्ट' में छपे लेख का हवाला देते हुए भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक त्रिकोण का खुलासा किया, जिसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस, न्यूज पोर्टल ओसीसीआरपी और कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हैं।

- भारतीय वैक्सीन की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ओसीसीआरपी ने 1 जुलाई को आर्टिकल लिखा और 2 जुलाई को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और कोवैक्सीन के खिलाफ अभियान चलाया। यहां पर, निर्देश ओसीसीआरपी का था और राहुल गांधी उस निर्देश का पालन किया।
- ओसीसीआरपी ने लगातार भारत के बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाया है, उनके विरुद्ध अनर्गल रिपोर्ट पेश की हैं। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे भी डगमगाया जाए और भारत के शेयर मार्केट को गिरा दिया जाए। इसके पीछे छिपे मंशा थी कि जब मार्केट क्रैश करेगा तो आम भारतीय के पैसे डूब जायेंगे और लोग सरकार का विरोध करके सत्ता परिवर्तन करा देंगे।
- देश पर आघात करने वाली जब भी ऐसी रिपोर्ट सामने आईं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के भीतर डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की बात की है। 18 जुलाई, 2021 को ओसीसीआरपी ने पेगासस रिपोर्ट को उजागर किया था और 19 जुलाई को राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन में हाहाकार मचाया। एक सोची समझी साजिश के तहत संसद सत्र से पहले ही ऐसी रिपोर्ट आती है और सदन में हंगामा करके स्थगित करा दिया जाता था।
- जुलाई, 2022 में नेशनल हेराल्ड के केस में मां-बेटे से ईडी पूछताछ कर रही थी तो ओसीसीआरपी ने एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही लीगल प्रोसीडिंग राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मां-बेटे ने 5 हजार करोड़ रुपये का गबन किया और ओसीसीआरपी ने अमेरिका में बैठकर उन्हें क्लीन चिट दे दी।
- जब ओसीसीआरपी को कोई नुकसान होता है, तो राहुल गांधी क्यों परेशान हो जाते हैं? जब राहुल गांधी को तकलीफ होती है, तो ओसीसीआरपी क्यों रोने लगती है? ओसीसीआरपी और राहुल गांधी भले ही अलग-अलग दिखते हों, लेकिन उनकी आत्मा एक है। अगर सही मायने में कहा जाए तो जॉर्ज सोरॉस और राहुल गांधी एक ही विचारधारा के दो चेहरे हैं।
- राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी वहां राहुल गांधी ने ओसीसीआरपी से जुड़े बांग्लादेशी पत्रकार मुश्फिकुल फजल अंसारी से मुलाकात की थी। अंसारी लंबे समय से भारत विरोधी लेख प्रकाशित करते रहे हैं। जहां देश का अहित हो, वहां राहुल गांधी मौजूद रहते हैं।
- दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान आनंद मगनाले ने चीन से पैसे लाकर शरजील इमाम को दिए, जो दंगों में शामिल था। आनंद मगनाले ओसीसीआरपी के पत्रकार भी हैं और राहुल गांधी के करीबी आदमी भी हैं। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता। ■

भारत में डिजिटल भुगतान में एक क्रांति- एक रिपोर्ट

विश्व में रीयल-टाइम भुगतान लेन-देन में 2023 तक भारत की हिस्सेदारी लगभग 49 प्रतिशत

अक्टूबर, 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने एक महीने में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन-देन को संसाधित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत करके देश के भुगतान इकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। यह प्रणाली निर्बाध निधि हस्तांतरण, व्यापारी भुगतान और पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाती है, जो उपयोगकर्ताओं को निर्धारित भुगतान अनुरोधों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करती है

यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेन-देन को तेज, सुरक्षित और सरल बना दिया है, बल्कि इसने आम लोगों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है, जिससे देश नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

यूपीआई के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं 632 बैंक

यूपीआई से अक्टूबर, 2024 में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन-देन के माध्यम से 23.49 लाख करोड़ रुपये का प्रभावशाली लेन-देन किया गया, जो अक्टूबर, 2023 में हुए 11.40 बिलियन लेन-देन की तुलना में 45 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इसके प्लेटफॉर्म से 632 बैंक जुड़े हैं तथा इसके उपयोग में यह वृद्धि भारत के भुगतान परिदृश्य में यूपीआई के बढ़ते प्रभुत्व को उजागर करती है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक आम लोग और व्यवसाय डिजिटल लेन-देन की सुविधा और सुरक्षा को अपना रहे हैं, लेन-देन की बढ़ती संख्या और मूल्य देश को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

यूपीआई से अक्टूबर, 2024 में 16.58 बिलियन वित्तीय लेन-देन के माध्यम से 23.49 लाख करोड़ रुपये का प्रभावशाली लेन-देन किया गया, जो अक्टूबर, 2023 में हुए 11.40 बिलियन लेन-देन की तुलना में 45 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इसके प्लेटफॉर्म से 632 बैंक जुड़े हैं तथा इसके उपयोग में यह वृद्धि भारत के भुगतान परिदृश्य में यूपीआई के बढ़ते प्रभुत्व को उजागर करती है

यूपीआई: चौबीसों घंटे पहुंच व निर्बाध एवं सुरक्षित भुगतान

यूपीआई ने अपनी सहजता, सुरक्षा और बहु-उपयोगिता के साथ भारत में डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से बदल दिया है। चौबीसों घंटे लेन-देन की सुविधा प्रदान करके और सिंगल-क्लिक भुगतान और वर्चुअल एड्रेस जैसी सुविधाएं प्रदान करके यह उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और गोपनीयता दोनों सुनिश्चित करता है। एक ऐप में कई बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करने की इसकी क्षमता इसे वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक गेम-चेंजर बनाती है।

यूपीआई की मुख्य विशेषताएं

- **चौबीसों घंटे पहुंच:** मोबाइल डिवाइस के माध्यम से वर्ष के 365 दिन, 24 घंटे तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा।
- **एकीकृत बैंकिंग पहुंच:** उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कई बैंक खातों तक पहुंच की अनुमति देता है।
- **निर्बाध एवं सुरक्षित भुगतान:** सिंगल क्लिक 2-फैक्टर प्रमाणीकरण प्रदान करता है, जो विनियामक अनुपालन और सुरक्षित एक-क्लिक पर लेन-देन सुनिश्चित करता है।
- **उन्नत गोपनीयता:** लेन-देन के लिए वर्चुअल एड्रेस का उपयोग होता है, जिससे खाता संख्या या आईएफएससी कोड जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती

है।

- **क्यूआर कोड एकीकरण:** क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से आसान भुगतान की सुविधा, त्वरित और सुरक्षित लेन-देन।
- **कैश-ऑन-डिलीवरी का विकल्प:** डिलीवरी के दौरान नकद भुगतान या तत्काल भुगतान की परेशानी को समाप्त करके लेन-देन को सरल बनाता है।
- **व्यापारी और इन-ऐप भुगतान:** व्यापारियों के लिए एकल एप्लिकेशन के माध्यम से या सीधे ऐप्स के भीतर भुगतान।
- **विविध भुगतान विकल्प:** इसमें उपयोगिता वाले बिलों का भुगतान, ओवर-द-काउंटर लेन-देन और स्कैन-एंड-पे सुविधाएं शामिल हैं।
- **लेन-देन में आसानी:** दान, संग्रह, संवितरण और बहुत कुछ आसानी से संभव होता है।
- **ग्राहक सहायता:** उपयोगकर्ताओं को मोबाइल एप्लिकेशन से सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

यूपीआई का प्रभाव

यूपीआई ने छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों और प्रवासी श्रमिकों पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें पैसे ट्रांसफर करने और भुगतान प्राप्त करने का एक आसान और कुशल तरीका मिल गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान इसका उपयोग विशेष रूप से तेज़ हुआ, क्योंकि लोगों ने नकद लेन-देन के लिए सुरक्षित, संपर्क रहित विकल्प तलाशे। हालांकि, यूपीआई की सफलता इसके बुनियादी ढांचे की मजबूती से कहीं आगे तक है। यह इसके द्वारा प्रेरित व्यवहारगत बदलाव से भी उपजी है, जहां प्रणाली में विश्वास और इसकी सुलभता इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने में प्रमुख कारक रहे हैं।

इस बदलाव को सुगम बनाने वाले छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक भुगतान ऐप्स द्वारा वॉयस बॉक्स का उपयोग है। ये डिवाइस आमतौर पर स्नैक कार्ट और चाय की दुकानों पर पाए जाते हैं, जो प्रत्येक क्यूआर कोड लेन-देन के साथ प्राप्त होने वाली धनराशि की घोषणा करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता जो अक्सर फ़ोन संदेशों की जांच करने में बहुत व्यस्त होते हैं, उन्हें अपनी कमाई के बारे में पता हो। इस सरल लेकिन प्रभावी सुविधा ने छोटे व्यापारियों का विश्वास जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पहले नकद लेन-देन के आदी थे और डिजिटल भुगतान से सावधान रहते थे।

यूपीआई की एक अन्य महत्वपूर्ण डिजाइन विशेषता यह है कि इसमें उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा भुगतान ऐप चुनने की सुविधा दी गई है, भले ही उनका खाता किसी भी बैंक में हो। इस आसानी ने उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान की है, जिससे उनके लिए यूपीआई को अपने भुगतान पद्धति के रूप में अपनाना आसान हो गया है।

रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ एकीकृत करना डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक और क्रांतिकारी कदम है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को लेन-देन के लिए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई दोनों के लाभों तक पहुंच की अनुमति देती है, जिससे वे बचत खातों से पैसे निकालने के बजाय अपनी क्रेडिट लाइनों के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

यूपीआई का वैश्विक विस्तार

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ रही है, क्योंकि यूपीआई और रुपे दोनों ही दूसरे देशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वर्तमान में यूपीआई सात देशों में जारी है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं।

फ्रांस में यूपीआई का आना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरोप में पहली बार उपयोग किया जा रहा है। यह विस्तार भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को विदेश में रहते हुए या यात्रा करते हुए भी सहजता से भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अपनी वैश्विक पहुंच से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिक्स समूह के भीतर यूपीआई के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया है, जिसमें अब छह नए सदस्य देश शामिल हो गए हैं। इस पहल से धन प्रेषण प्रवाह को और बढ़ावा मिलने, वित्तीय समावेशन में सुधार होने और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारत का कद और उंचा होने की उम्मीद है।

एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 तक विश्व में रीयल-टाइम भुगतान लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 49 प्रतिशत है, जो डिजिटल भुगतान नवाचार में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। यूपीआई की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और डिजिटल लेन-देन में निरंतर वृद्धि के साथ भारत वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।

सार-संक्षेप

निष्कर्षतः, यूपीआई ने न केवल भारत में वित्तीय लेन-देन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, बल्कि देश को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी स्थापित किया है। लोगों और व्यवसायों दोनों के लिए एक निर्बाध, सुरक्षित और सुलभ मंच प्रदान करके यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेन-देन की संख्या और भौगोलिक पहुंच दोनों के संदर्भ में इसकी उल्लेखनीय वृद्धि वित्तीय परिदृश्य पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है। जैसे-जैसे यूपीआई वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार कर रहा है, यह डिजिटल भुगतान के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है, देश के नागरिकों को सशक्त बना रहा है, आर्थिक अवसरों को बढ़ा रहा है और वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव में योगदान दे रहा है। ■

पिछले पांच वर्षों में 60 जिले वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से हुए मुक्त

2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है। परिणामी मौतों (सुरक्षा बल+सिविलियन) की संख्या भी 2010 के 1005 से घटकर 2023 में 138 हो गई है, जोकि 86 प्रतिशत की कमी है

पिछले पांच वर्षों के दौरान 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से मुक्त कराया गया है तथा वर्तमान में देश के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित हैं। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने 4 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सरकार के विषय हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए 2015 में 'वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है।

पिछले 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के बीच विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजनाओं के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4350.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के तहत पिछले 5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान हेलीकॉप्टरों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास की दृष्टि से कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए अब तक 14529 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- दूरसंचार कनेक्टिविटी सुधार के लिए 6524 टावर लगाए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए 5731 डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं।
- कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) कार्यरत हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) कार्यात्मक बनाए गए हैं।

नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में कमी और भौगोलिक विस्तार के संकुचन दोनों के संदर्भ में वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है। परिणामी मौतों (सुरक्षा बल+सिविलियन) की संख्या भी 2010 के 1005 से घटकर 2023 में 138 हो गई है, जोकि 86 प्रतिशत की कमी है। वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य में सुधार के कारण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल, 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई। जुलाई, 2021 में 70 तथा अप्रैल, 2024 में और घटकर 38 हो गई है। ■

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2024 तक 43,30,121 खाते खोले गए

महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (एमएसएससी) 'आजादी का अमृत महोत्सव' के यादगार के रूप में 31 मार्च, 2023 को शुरू की गई थी। 31 अक्टूबर, 2024 तक इसके अंतर्गत 43,30,121 खाते खोले जा चुके हैं। यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 3 दिसंबर को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

सरकार ने इस योजना को आकर्षक ब्याज दर पर देश की महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और निर्धारित वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू किया था। इस महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत खाता किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च, 2025 तक या उससे पहले खोला जा सकता है।

योजनाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह खाता न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपये के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए खोला जा सकता है।
- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के लिए ब्याज दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है जो तिमाही आधार पर संयोजित होकर खाते में जमा कर दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर आंशिक निकासी और समयपूर्व बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ■

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने 21,772 करोड़ रुपये के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दी

तटीय क्षेत्रों में निगरानी के लिए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस), नेक्स्ट जेनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ने 3 दिसंबर, 2024 को 21,772 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 5 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने भारतीय नौसेना के लिये 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की खरीद के लिये आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान

> रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को भी मंजूरी दे दी

की। इन्हें तट के करीब कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, निगरानी, गश्ती और खोज और बचाव (एसएआर) कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जहाज एंटी-पायरेसी मिशनों में विशेष रूप से हमारे द्वीप और उसके आसपास क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को भी मंजूरी दे दी। ये जहाज कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम हैं, जिसमें तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट, पनडुब्बियों जैसी उच्च मूल्य इकाइयों को एस्कॉर्ट करना शामिल है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् द्वारा एक्सटर्नल एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, नेक्स्ट जेनरेशन राडार वार्निंग रिसीवर और एसयू-30 एमकेआई विमान के लिए संबद्ध उपस्करों वाले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस) की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान किया गया था। यह प्रणाली एसयू-30 एमकेआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित दुश्मन के लक्ष्यों के खिलाफ एक मिशन को पूरा करते हुए दुश्मन के रडार और संबंधित हथियार प्रणाली से इसकी रक्षा करेगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् ने तटीय क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एम (एमआर) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी। इसने टी-72 और टी-90 टैंकों, बीएमपी और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहाल के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिससे इन परिसंपत्तियों की सेवा जीवन में वृद्धि होगी। ■

कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की दी मंजूरी

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का घर है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर को नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी।

एआईएम 2.0, विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती तथा और गहराई प्रदान करना है।

यह मंजूरी भारत में एक मजबूत नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्लोबल

> अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) जैसी एआईएम 1.0 की उपलब्धियों पर आगे बढ़ते हुए एआईएम 2.0 मिशन के दृष्टिकोण में बड़े गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है

इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का घर है। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम 2.0) के अगले चरण से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में और बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। एआईएम के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी।

अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) जैसी एआईएम 1.0 की उपलब्धियों पर आगे बढ़ते हुए एआईएम 2.0 मिशन के दृष्टिकोण में बड़े गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है। एआईएम 1.0 में ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया शामिल थी, जिन्होंने भारत के तत्कालीन उभरते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नए नवाचार बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, जबकि एआईएम 2.0 में मौजूदा वातावरण में कमियों को दूर करने और केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई नई पहल शामिल है। एआईएम 2.0 को भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को तीन तरीकों से मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है: (a) इनपुट बढ़ाकर (यानी, अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को शामिल करके), (b) सफलता दर या 'थ्रूपुट' में सुधार करके (यानी, अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके) और (c) 'आउटपुट' की गुणवत्ता में सुधार करके (यानी, बेहतर नौकरियों, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करके) ■

कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ओएनओएस) को दी मंजूरी

इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और सभी विषयों के वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाली विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं में उपलब्ध ज्ञान का भंडार खुल जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर को विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' को मंजूरी दे दी। इस योजना को एक सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' की सुविधा प्रदान करेगी।

एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की सीमा के दायरे और पहुंच का विस्तार करेगा। यह योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ पहल की पूरक होगी।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को एक केंद्रीय एजेंसी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिबनेट) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है। इस सूची में 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं, जिसका अर्थ है— लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता संभावित रूप से एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना का लाभ उठा सकेंगे।

यह विकसितभारत@2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह पहल टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल प्रवासी समुदाय के लिए विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करेगी, जिससे देश में प्रमुख विषयों के साथ-साथ अंतःविषय अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। एएनआरएफ समय-समय पर एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना के उपयोग तथा इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा।

उच्च शिक्षा विभाग के पास 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' के नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। एएनआरएफ समय-समय पर एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना के उपयोग तथा इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा। डीएचई और अन्य मंत्रालय, जिनके प्रबंधन में उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं, संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच एक राष्ट्र, एक सदस्यता की उपलब्धता और पहुंच के तरीके के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में इस सुविधा का बेहतर उपयोग होगा। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं द्वारा इस अनूठी सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने स्तर पर अभियान चलाएं। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 25 नवंबर को आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार 1435 करोड़ रुपये आएगा।

पैन 2.0 परियोजना करदाता नामांकन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसके महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं:

- बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और तेज सेवा प्रदान करना
- सत्य और डेटा स्थिरता का एकमात्र स्रोत
- पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं तथा लागत समायोजन
- अधिक दक्षता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अनुकूलन

पैन 2.0 परियोजना करदाताओं के उन्नत डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता नामांकन सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए एक ई-गवर्नेंस परियोजना है। यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम का अपग्रेड होगा, जो कोर और नॉन-कोर पैन/टैन गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को एकीकृत करेगा।

पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल भारत में एक समावेशी सरकार की दृष्टि का प्रतिध्वनित करती है। ■

शून्य मामला: भारत की पोलियो उन्मूलन महागाथा

भारत को 2014 में पोलियो मुक्त होने का दर्जा मिलना वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। पोलियो उन्मूलन कोई एक दिन की सफलता नहीं, बल्कि दशकों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है, जिसका आरंभ वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (जीपीईआई) से भारत के जुड़ने और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों से पूरा हुआ। नए टीके के एकीकरण, नई निगरानी प्रणालियों और सरकार के नेतृत्व वाले टीकाकरण अभियानों ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि भारत सरकार के अथक प्रयासों और प्रमुख वैश्विक संगठनों के साथ साझेदारी से संभव हुई, जिनमें यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) शामिल हैं

भारत में टीकाकरण

भारत के टीकाकरण का आरंभ 1978 में हुआ, जब व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाना था। 1985 में इस कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) नाम दिया गया, जिसे शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। बदलते समय के साथ यूआईपी कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल का अभिन्न अंग बन गया, जिसमें ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए 2005 में आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) भी शामिल है।

यूआईपी आज विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें सालाना 2.67 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल होती है और टीकाकरण से निवारणीय 12 बीमारियों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। यूआईपी के तहत लक्षित बीमारियों में पोलियो को सबसे पहले रखा गया था और अब इसका उन्मूलन सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है।

पोलियो उन्मूलन चरण की प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का आरंभ

1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के आरंभ के साथ ही पोलियो उन्मूलन की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 1994 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर पहला टीकाकरण अभियान चलाया गया जो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का अग्रिम चरण था। इस अभियान में ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) इस्तेमाल किया गया, जिसके अन्तर्गत 10 लाख से अधिक बच्चों तक इसकी खुराक पहुंचाई गई और सुनिश्चित किया गया कि पांच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को इसकी खुराक पिलाई जाए। बाद में यही सफलता पूरे देश में दोहराई गई।

'दो बूंद जिंदगी की' के नारे के साथ यह अभियान पोलियो उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयासों का पर्याय बन गया।

नियमित टीकाकरण और प्रणाली सुदृढ़ीकरण

पल्स पोलियो अभियान सामूहिक टीकाकरण के लिए आवश्यक था ही, भारत ने इसके साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत अपने नियमित टीकाकरण प्रयासों को भी सुदृढ़ बनाया। यूआईपी के अंतर्गत पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी की रोकथाम और तपेदिक के निःशुल्क टीके प्रदान कर सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को ये टीके लगाएं जाएं। भारत का लक्ष्य इन निरंतर प्रयासों से प्रतिरक्षा का उच्च स्तर बनाए रखना और टीके से नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारियों को फिर से उभरने से रोकना था।

भारत ने शीत भंडारण (कोल्ड चेन) प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे टीकों को सही तापमान पर संगृहीत और परिवहन करना सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रीय कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र (एनसीसीटीई) और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) स्थापित किए जाने से वैक्सीन भंडारण और वितरण व्यवस्था बेहतर तरीके से अंजाम देने में मदद मिली है।

निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) का प्रारंभ (2015)

वैश्विक पोलियो उन्मूलन रणनीति के अनुरूप भारत ने पोलियो उन्मूलन की अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2015 में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) देना आरंभ किया। आईपीवी पोलियो के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, खासतौर पर टाइप 2 पोलियो वायरस से निपटने में यह काफी कारगर रहा है। पहले धीरे-धीरे

छह राज्यों में आरंभ किए जाने के बाद इसे वर्ष 2016 तक पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया। वैश्विक स्तर पर ट्राइवेलेंट ओपीवी (टीओपीवी) से बाइवेलेंट ओपीवी (बीओपीवी) में बदलाव के बाद यह परिवर्तन आवश्यक हो गया था, जिसमें टाइप 2 स्ट्रेन शामिल नहीं था। आईपीवी ने इसमें निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की।

निगरानी और देखरेख

भारत की पोलियो उन्मूलन सफलता काफी हद तक कठोर निगरानी प्रणालियों के कारण संभव हुई, जिसमें एक्यूट फ्लेसीड पैरालिसिस (एएफपी) निगरानी और आसपास के माहौल की निगरानी शामिल रही है। निगरानी से भारत को किसी भी पोलियो प्रसार का प्रकोप तुरंत पता लगाने और इससे निपटने के उपायों में मदद मिली।

एएफपी निगरानी : इस प्रणाली में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अस्पष्टीकृत पक्षाघात के मामलों की निगरानी की जाती है, क्योंकि यह पोलियो का एक सामान्य लक्षण है।

आसपास के माहौल की निगरानी : पोलियोवायरस का पता लगाने के लिए सीवेज के पानी की निगरानी करने से उन स्थानों की पहचान करने में भी मदद मिली जहां वायरस का फैलाव है। उच्च स्तर की निगरानी रखकर भारत किसी भी अवशिष्ट पोलियोवायरस संचरण का पता लगाकर उसे नियंत्रित कर सका।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक सहभागिता

भारत में पोलियो उन्मूलन की सफलता का एक मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति रही। सभी स्तरों पर राजनीतिक नेताओं ने निरंतर समर्थन दिया और यह सुनिश्चित किया कि इसके लिए संसाधन आवंटित हो और इस कार्यक्रम पर आवश्यक ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, सामुदायिक सहभागिता की भी पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और स्थानीय नेताओं ने इसके उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद की। उन्होंने टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों को बताया और सुनिश्चित किया कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी बच्चों को टीका लगाया जाए। पल्स पोलियो अभियान घर-घर जाकर टीकाकरण प्रयासों पर बहुत निर्भर था और इसी से दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचा जा सका।

प्रमाणन और निर्णायक उन्मूलन

2011 में भारत में पोलियोवायरस का अनियंत्रित अंतिम मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पाया गया। उसके बाद देश ने अपने निगरानी प्रयासों को और बढ़ा दिया और रोकथाम के उपायों के बाद अनियंत्रित पोलियो वायरस का कोई और मामला सामने नहीं आया।

भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणन के लिए उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कड़े मानदंडों को पूरा करना पड़ा। इनमें तीन साल तक अनियंत्रित पोलियो वायरस संक्रमण न फैलना, मजबूत निगरानी प्रणाली और वायरस के किसी बचे अंश को समाप्त करना शामिल था। इस कठोर प्रमाणन प्रक्रिया में क्षेत्रीय पोलियो प्रमाणन आयोग द्वारा व्यापक जांच और मूल्यांकन शामिल था।

27 मार्च, 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया। यह देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का उदाहरण है।

प्रमाणन उपरांत: सतर्कता एवं सुरक्षा!

पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद भी भारत इस स्थिति को बनाए रखने के कई निवारक उपाय कर रहा है:

वार्षिक पोलियो अभियान : भारत उच्चतम प्रतिरक्षण स्तर बनाए रखने और इससे किसी बच्चे के न छूटने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एसएनआईडी) का आयोजन करता है।

निगरानी और सीमा पर टीकाकरण : एएफपी और पर्यावरण निगरानी के माध्यम से निरंतर निगरानी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर टीकाकरण कर स्थानिक क्षेत्रों से पोलियो के फिर से पहुंचने का जोखिम कम करने का अभियान जारी है।

नए टीके और विस्तार : आईपीवी के अतिरिक्त भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कई नए टीके लगाने शुरू किए हैं, जिनमें रोटावायरस, न्यूमोकोकल, कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) और मीजल्स-रूबेला (एमआर) वैक्सीन शामिल हैं। ये अन्य टीका-निवारक रोगों की रोकथाम के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।

मिशन इंद्रधनुष : 2014 में आरंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष (एमआई) का लक्ष्य टीकाकरण को 90 प्रतिशत तक विस्तारित करना है। इसमें अल्प टीकाकरण दर वाले दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यापक मिशन इंद्रधनुष चरण में टीकाकरण की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बाल स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई है।

निष्कर्ष

पोलियो मुक्त भारत की यात्रा दृढ़ संकल्प, सहयोग और नवाचार की उल्लेखनीय गाथा है। देश की यह उपलब्धि सामूहिक टीकाकरण अभियान, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रभावी निगरानी प्रणाली और सामुदायिक प्रयासों का परिणाम रहा है। निरंतर सतर्कता बरतने और सतत टीकाकरण प्रयासों से भारत पल्स पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने और पोलियो को हमेशा के लिए समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के पल्स पोलियो कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यह प्रभावी व्यवस्था, सुदृढ़ नीति और सामुदायिक भागीदारी के समर्थन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। ■

मोदी स्टोरी

जब युवा मोदी ने केवल दो जोड़ी कपड़े के साथ अमेरिका का दौरा किया

—डॉ. पन्ना बरई, अमेरिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा से ही एक सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। 1993 में वह अमेरिका गए और भारतीय मूल के चिकित्सक दंपत्ति डॉ. भरत और पन्ना बरई के साथ रहे। डॉ. पन्ना बरई बताती हैं कि जब श्री मोदी अमेरिका आए थे, तो श्री मोदी ने उनसे कहा था कि वह एक 22 इंच का सूटकेस एवं केवल दो जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन अपने कपड़ों को धोना पड़ता है, यह एक असामान्य बात थी, क्योंकि अमेरिका में लोग आम तौर पर सप्ताह में एक बार कपड़े धोते हैं। डॉ. बरई बताती है, "इससे हमें पता चला कि वह

कितने सरल एवं विनम्र थे और आज भी हैं... यह उनकी सादगी के बारे में बहुत कुछ कहता है, उनके प्रसिद्धि पाने के बाद भी यह एक सच्चाई है।"

उन्होंने बताया कि श्री मोदी का अपने देश के प्रति प्रेम उनकी बातचीत में स्पष्ट रूप से झलकता था। डॉ. बरई कहती है, "वह जिस देश से प्यार करते थे, उसके बारे में इतनी संवेदनशीलता एवं जुनून के साथ बात करते थे कि हम अक्सर ऐसी किसी बातचीत के दौरान स्वभाविक तौर पर उनकी आंखों में आंसू देख सकते थे, जब वह चर्चा करते थे कि तो वह इस बात का जिक्र अक्सर करते थे कि भारत के लिए क्या किया जाना चाहिए।" ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

आर. मोहन राव

श्री आर. मोहन राव अंडमान एवं निकोबार के एक छोटे व्यवसायी थे, इसी दौरान वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क में आए। वह नियमित रूप से संघ की शाखाओं में जाया करते थे एवं भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर अंडमान एवं निकोबार में इसके सदस्य बन गए।

श्री मोहन ने पार्टी में विभिन्न पदों पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ वह विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा बने और कई युवाओं को पार्टी से जोड़ा। कैम्पबेल बे जैसे एक एकांत द्वीप में भाजपा की स्थापना के लिए श्री मोहन ने संस्थापक सदस्य एवं तीन बार के सांसद श्री बिष्णु पद रे जी के साथ विभिन्न यात्राओं में भाग लिया। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में बैठकें कीं और वहीं विश्राम भी किया। धीरे-धीरे लोग पार्टी से जुड़ने लगे और अपने घरों में ही उनके खाने-पीने एवं विश्राम का प्रबंध करने लगे। इस तरह कार्यकर्ता जुड़ते गए और कारवां बनता गया। श्री मोहन ने सरदार पटेल की प्रतिमा के निर्माण के लिए लोहा इकट्ठा करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी उपस्थिति हमेशा युवाओं एवं पूरे द्वीप में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत रही। ■

श्री आर. मोहन राव
जन्म: 10 नवंबर, 1968
सक्रिय वर्ष: 2010-2012
जिला: पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया-फर्स्ट' नीति और 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की रूस की इच्छा से अवगत कराया तथा एसएमई के विकास के लिए रूस-भारत सहयोग पर जोर दिया

राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया फर्स्ट' नीति और 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने विकास के लिए स्थिर माहौल को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन नीतियों ने भारत के विकास में किस तरह योगदान दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति श्री पुतिन की टिप्पणियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति को चिन्हित किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए 'स्थिर स्थिति' बनाने को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। श्री पुतिन ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आर्थिक पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया।

भारत में निवेश लाभदायक है: राष्ट्रपति पुतिन

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम और भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के बीच समानताएं बताते हुए भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के प्रति रूस की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश लाभदायक है। श्री पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के नेतृत्व ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री मोदी के पास 'मेक इन इंडिया' नामक एक ऐसा ही कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार 'इंडिया फर्स्ट' की नीति से प्रेरित होकर स्थिर स्थितियां बना रही है। हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना लाभदायक है।" उन्होंने यह भी कहा कि रूसी कंपनी रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने ब्रिक्स के उदय के संदर्भ में रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसमें एसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा ब्रिक्स व अन्य

देशों में एसएमई के लिए सुचारू व्यापारिक लेन-देन की सुविधा के लिए त्वरित विवाद समाधान प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उन्होंने बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों के स्थान पर नए रूसी ब्रांडों के उदय की ओर इशारा किया तथा उपभोक्ता वस्तुओं, आईटी, उच्च तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय रूसी निर्माताओं की सफलता के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, "हमारे लिए, यह हमारे आयात घटाने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नए रूसी ब्रांडों के उभरने से उन पश्चिमी कंपनियों की जगह लेने में मदद मिल रही है, जो स्वेच्छा से हमारे बाजार को छोड़ चुकी हैं। हमारे स्थानीय निर्माताओं ने न केवल उपभोक्ता वस्तुओं में बल्कि आईटी और उच्च तकनीक वाले उद्योगों में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।"

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने एसएमई के विकास को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच और अधिक सहयोग का भी आग्रह किया। उन्होंने सदस्य देशों को अगले साल ब्राजील में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग कायम करने की दिशा में प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। रूस द्वारा ब्रिक्स के साथ मिलकर विकसित किए जा रहे निवेश मंच के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति श्री पुतिन ने कहा कि इसमें सभी भागीदार देशों को लाभ पहुंचाने की क्षमता है और उम्मीद है कि यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और वैश्विक दक्षिण और पूर्व के देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा। ■

टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत का बेहतर प्रदर्शन

जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश से टीबी के उन्मूलन का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक नया मॉडल अपनाया गया, जिसके तहत भारत ने पिछले कुछ वर्षों में टीबी की रोकथाम, निदान एवं उपचार के तरीकों में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रयास किया, जो हमारे अभिनव दृष्टिकोणों से प्रेरित है। डब्ल्यूएचओ की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 हमारे इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को स्वीकार करती है। इसने 2015 से 2023 तक भारत में टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत की गिरावट देखी है - जो वैश्विक स्तर पर देखी गई गिरावट से दोगुनी है। इतना ही नहीं, इस दौरान 25.1 लाख रोगियों का उपचार किया गया, जो 2015 में 59 प्रतिशत से 2023 में 85 प्रतिशत तक उपचार कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर 7 दिसंबर को भारत ने अपनी टीबी उन्मूलन रणनीति में एक और परिवर्तनकारी कदम उठाया। हम टीबी के खिलाफ इस जंग में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए देश भर के 347 ऐसे जिलों, जहां टीबी के मरीजों की संख्या अधिक है, वहां 100 दिवसीय अभियान शुरू कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से हम हर टीबी रोगी की जल्द पहचान करने और समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। जनभागीदारी की सच्ची भावना से प्रेरित होकर, हम सभी - निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वास्थ्य चिकित्सक, नागरिक समाज, निगम और समुदाय - को इस अभियान से जोड़कर उनसे सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं।

अपने प्रयासों को को पूर्णता देने और टीबी रोगियों के स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत ने पोषण सहायता योजना- निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) को आरंभ किया है। अप्रैल, 2018 से हमने एनपीवाई के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1.16 करोड़ लाभार्थियों को 3,295 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। टीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए इस योजना के तहत मासिक सहायता को नवंबर, 2024 से 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) ने न केवल पोषण की चुनौती से निपटने में मदद की है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी की भावना को भी बढ़ाया है। इस अभियान ने जागरूकता बढ़ाने एवं टीबी रोगियों को पोषण, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न सामुदायिक हितधारकों को एकजुट किया है। जनभागीदारी की भावना से प्रेरित इस सरकार-नागरिक सहयोग के तहत देश भर में 1.75 लाख निक्षय मित्रों ने टीबी रोगियों को 21 लाख भोजन पैकेट उपलब्ध करवाये गये हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उपचार की सफलता दर में सुधार के लिए बेडाक्विलाइन और डेलामैनिड जैसी नई दवाएं भारत में लाने का फैसला किया है। दवा-प्रतिरोधी वेरिएंट वाले रोगियों के लिए उपचार पूरा करने में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए,हमने एक नये छोटे रेजिमेन, BpaLM को अनुमति दी है, जो मौजूदा रेजिमेन की तुलना में अधिक प्रभावी है, जबकि हमारे पास पारंपरिक 19-20 महीने के रेजिमेन के साथ-साथ 9-11 महीने की छोटी अवधि के रेजिमेन भी उपलब्ध है। BPaLM रेजिमेन के साथ रोगी अब केवल छह महीने में उपचार पूरा कर लेंगे!

हमने लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जमीनी स्तर पर उन्नत उपकरण उपलब्ध हों, ताकि सभी रोगियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके और उनका इलाज किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने अधिक कुशल एवं सटीक निदान उपकरण - मालिक्यूलर टेस्ट को आरंभ किया है। 2014-15 में कुछ सौ

मशीनों से अब हमारे पास सभी जिलों में 8,293 मालिक्यूलर निदान मशीनें उपलब्ध हैं।

दरअसल, मेक इन इंडिया पहल से प्रेरणा लेते हुए, स्वदेशी मालिक्यूलर टेस्ट को लाया गया और उन्हें अपनाया गया। हम न केवल जिला और ब्लॉक स्तर पर टीबी के निदान में लगने वाले समय को कम करने में सक्षम हुए हैं, बल्कि परीक्षण एवं उपचार की लागत में भी भारी कमी आयी है। हमारे स्वदेशी मालिक्यूलर टेस्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है। इन पहलों ने भारत को टीबी के खिलाफ इस वैश्विक जंग में एक सच्चे नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्थापित किया है।

हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) 2018 से लगातार दुनिया भर में टीबी अनुसंधान के शीर्ष सार्वजनिक वित्तपोषक संस्थानों में से एक रहा है। हम अधिक कुशल पीओसी डायग्नोस्टिक्स सहित नए उपकरणों को तेजी से विकसित करने एवं उन्हें क्रियांवित करने के लिए निवेश कर रहे हैं।

टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की यात्रा उसके नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। अग्रणी अनुसंधान से लेकर उन्नत निदान एवं उपचार तक, सार्वभौमिक सामाजिक सहायता प्रावधानों की शुरुआत तक, भारत वैश्विक टीबी के खिलाफ इस जंग में सबसे आगे है। समय की मांग है कि टीबी की पहचान, निदान, उपचार एवं रोकथाम में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। 100 दिनों का सघन अभियान टीबी को खत्म करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं अन्य सभी हितधारकों की भागीदारी से हम मानवता के इस महान दुश्मन को हरा देंगे और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेंगे। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं)

भारत में टीबी मामले 2015 की तुलना में 2023 में 17.7 प्रतिशत कम हुए

भारत में टीबी के मामलों में 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 237 से 2023 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 195 हुए यानी 17.7 प्रतिशत की कमी; टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 21.4 प्रतिशत कमी, 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 मौतें, 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 22 मौतें

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। भारत में टीबी की घटना दर 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 237 से 2023 में 195 प्रति 100,000 जनसंख्या पर 17.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। टीबी से होने वाली मौतें 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 2023 में 21.4 प्रतिशत घटकर 22 प्रति लाख जनसंख्या पर आ गई हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने 3 दिसंबर को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में चलाया जाता है। यह देश भर में टीबी उन्मूलन (2017-25) के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को लागू करता है।

एनटीईपी के अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रयास और हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च संख्या वाले टीबी मामलों के क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
- टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां और निदान की सुविधा उपलब्ध कराना।
- प्रमुख संवेदनशील और सह-रुग्ण आबादी में अभियान के माध्यम से सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाना।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी टीबी जांच और उपचार सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-जिला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कवरेज का विस्तार।
- कलंक की भावना को मिटाने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सम्बंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) हस्तक्षेप।
- टीबी उन्मूलन के लिए सम्बंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करना।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों और कमजोर आबादी को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों पर नज़र रखना।
- नि-क्षय मित्र पहल के अंतर्गत टीबी रोगियों और घर के लोगों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। ■

'सहकार से समृद्धि' का भारतीय दर्शन

अमित शाह

सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता का स्वायत्त मंत्रालय स्थापित कर सहकारिता के लिए अवसरों के सारे बंद दरवाजे खोल दिए।

महज तीन वर्षों में देश में सहकारिता को तेज गति मिली है। इसी कड़ी में भारत का सहकारिता आंदोलन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। राजधानी दिल्ली 25-30 नवंबर के बीच में 'अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) महासभा' और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है।

आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत इसका आयोजक होगा। इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ होगा। आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रतीक है।

मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार मानती है कि यह परिवर्तन सहकारिता आंदोलन को मजबूत किए बिना नहीं हो सकता। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने सहकारी आंदोलन के पुनरुत्थान की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री जी ने 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया है, जिसका उद्देश्य देश की सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। दुनिया के अन्य देशों के लिए यह एक विकास मॉडल के रूप में सामने आएगा।

प्रधानमंत्री जी ने 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया है, जिसका उद्देश्य देश की सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा

भारत में प्राचीन काल से सहकारिता का समृद्ध इतिहास रहा है, जिसके संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी 'निधियों' का प्रचलन सहकारी वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कई अर्थशास्त्रियों ने 21वीं सदी की शुरुआत में ही यह चर्चा प्रारंभ की दी थी कि सहकारिता का विचार आधुनिक युग में कालबाह्य हो गया है। मेरा मानना है कि भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में छोटी जनसंख्या वाले देशों का आर्थिक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता।

आर्थिक विकास के सभी मानकों में वृद्धि के साथ यह जरूरी है कि 140 करोड़ लोगों की समग्र समृद्धि हो जो सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक ने गत 100 वर्षों में 100 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। बैंक न केवल एनपीए को शून्य बनाए रखने में सफल रहा, बल्कि उसके पास 6,500 करोड़ से अधिक जमाराशि भी है।

अमूल भी सहकारी आंदोलन का उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्तमान में इससे 35 लाख परिवार सम्मान और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इन परिवारों की महिलाएं अग्रिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परिणामस्वरूप, आज अमूल का वार्षिक कारोबार 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं में से किसी ने भी 100 रुपये से अधिक का प्रारंभिक निवेश नहीं किया था।

सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 60 से अधिक पहलों पर काम शुरू किया है। दशकों की उपेक्षा और प्रशासनिक कुरीतियों के परिणामस्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) आर्थिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो गई थीं। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने

का काम शुरू किया।

इनके लिए नए बाय-ला अपनाने से अब पैक्स डेरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र आदि जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हुए हैं। तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता का क्षितिज और व्यापक हुआ है।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने विदेशी बाजारों तक सहकारी उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाया तो राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड ने जैविक प्रमाणीकरण और बाजार का मंच तैयार किया।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने उन्नत बीजों की सुलभता सुनिश्चित की है। वित्तीय सहायता, कर राहत और इथेनाल मिश्रण कार्यक्रम से सहकारी चीनी मिलें समृद्ध हो रही हैं। सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहकारी संस्थाओं के पैसे को सहकारी बैंकों में ही जमा करने पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के जरिये सहकारी समितियों को पारदर्शी बनाने और प्रक्रिया को आसान बनाने से देश के सहकारी रूप से कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की पहुंच बनी है। इसके अतिरिक्त सरकार एक समग्र और व्यापक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर भी काम कर रही है।

आईसीए महासभा एवं वैश्विक सम्मेलन का मंच भारत के सहकारी आंदोलन द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु भारत के अभूतपूर्व प्रयासों को रेखांकित करेगा। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा ऐसे तंत्र का निर्माण है, जो सहकारी समितियों को उभरती चुनौतियों का सामना करने और अवसरों के उपयोग के लिए सशक्त बनाए।

इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के अवसर पर मैं विश्व के सहकारी नेताओं, नीति निर्माताओं और मानव विकास के पक्षधरों का आह्वान करता हूं कि हम सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सीखने, साझा करने और सहकार की भावना के साथ एकजुट हों। 'सहकार से समृद्धि' को लेकर भारत की प्रतिबद्धता सामूहिक समृद्धि-साझा प्रगति जैसे मूल्यों पर आधारित उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है। ■

(लेखक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं)

'न्याय संहिता' समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के आदर्शों से बुनी गई है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 दिसंबर को चंडीगढ़ में परिवर्तनकारी तीन नए आपराधिक कानूनों— भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ की पहचान देवी मां चंडी से जुड़ी है, जो शक्ति का एक रूप है जो सत्य और न्याय की स्थापना करती है। उन्होंने कहा कि यही दर्शन भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे स्वरूप का आधार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का लागू होना एक शानदार क्षण है, क्योंकि राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण मोड़ पर है और साथ ही भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो हमारे संविधान ने देश के नागरिकों के लिए परिकल्पित किए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश की नई न्याय संहिता बनाने की प्रक्रिया, दस्तावेज जितनी ही व्यापक रही है। उन्होंने कहा कि इसमें देश के कई महान संविधान विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत शामिल है।

श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता-पूर्व के कालखंड में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आपराधिक कानूनों को उत्पीड़न और शोषण के हथियार के रूप में देखा जाता था। उन्होंने कहा कि 1857 में देश के पहले बड़े स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया और फिर सीआरपीसी की पहली संरचना अस्तित्व में आई। श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों की अवधारणा के साथ-साथ इसका उद्देश्य भारतीयों को दंडित करना और उन्हें गुलाम बनाना था।

न्याय संहिता को समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय की अवधारणा से बुना गया बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि कानून की नजर में सभी समान होने के बावजूद व्यावहारिक वास्तविकता अलग है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग कानून से डरते हैं, यहां तक कि वे अदालत या पुलिस थाने में जाने से भी डरते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई न्याय संहिता समाज के मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को यह भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान में दिए गए सच्चे सामाजिक न्याय को दर्शाता है। ■

महाराष्ट्र का संदेश

शिव प्रकाश

लोकसभा 2024 के हुए चुनावों के परिणाम के आधार पर महाविकास अघाड़ी विधानसभा के परिणाम को भी अपने पक्ष में मान रही थी। लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें एवं विधानसभा की 151 सीटों पर बढ़त मिली थी। महायुति के समर्थन में आया यह जनादेश महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करेगा। साथ ही, देश की जनता को भी अनेक प्रकार की सीख देने वाला बनेगा

अभी-अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई। महायुति गठबंधन को 49.8% मत एवं 234 सीटें प्राप्त हुईं। गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी ने 148 सीटें लड़कर उसमें से 132 सीटें प्राप्त कीं, जो 90% स्ट्राइक रेट को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी की भी अभी तक की ये सबसे बड़ी सफलता है। इसी अप्रत्याशित सफलता के कारण महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाये।

लोकसभा 2024 के हुए चुनावों के परिणाम के आधार पर महाविकास अघाड़ी विधानसभा के परिणाम को भी अपने पक्ष में मान रही थी। लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें एवं विधानसभा की 151 सीटों पर बढ़त मिली थी। महायुति के समर्थन में आया यह जनादेश महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करेगा। साथ ही, देश की जनता को भी अनेक प्रकार की सीख देने वाला बनेगा।

महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जिसने समाज में चलने वाली अनेक विषमतायुक्त कुरीतियों को तोड़कर समरसतायुक्त समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। समाज में अलग-अलग प्रकार से भक्ति की धारा बहाने वाले संतों की भूमि महाराष्ट्र है। मुगलों की सत्ता को धूल चटाने वाले हिन्दवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र से ही सम्पूर्ण देश को स्वराज एवं स्वधर्म के संरक्षण की प्रेरणा दी। समरस समाज निर्माण के आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, महिला शिक्षा को समर्पित सावित्रीबाई फुले व छत्रपति शाहू जी महाराज की कर्मभूमि भी यही प्रदेश है। दलितोद्धार के महानायक भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की प्रारम्भिक कर्मभूमि भी महाराष्ट्र ही है। देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांतिकारी एवं अहिंसावादी दोनों ही माध्यमों से अपना योगदान देने वाले महापुरुषों की भूमि यह प्रदेश है। महानतम क्रांतिकारी वीर सावरकर एवं लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश के युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। इन समस्त महापुरुषों की प्रेरणा अपने में समाहित किए, देशभक्ति जागरण एवं हिंदुत्व के संस्कारों का पुंज बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्मस्थान नागपुर भी इसी प्रदेश में है, जो सज्जनशक्ति की आस्था का केंद्र बनकर अपने देश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है।

महाराष्ट्र के कुछ सत्तालोलुप नेता इन सभी महापुरुषों को नकारने का कार्य सदैव से कर रहे हैं। अपने को जातिगत राजनीति का केंद्र बिंदु मानने वाले लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारने का काम करते रहे। इतिहास की पुस्तकों में शिवाजी महाराज को लुटेरा कहने जैसे सिद्धांत पुस्तकों में प्रकाशित कर गढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। समर्थ स्वामी रामदास महाराज, दादाजी कोंडदेव की शिवाजी महाराज के

जीवन में कोई भूमिका नहीं है, यह सिद्धांत भी स्थापित करने का प्रयास होता ही रहा है। वीर सावरकर की देशभक्ति पर प्रश्न खड़े करना जैसे एक परंपरा ही बन गई है। महापुरुषों को जाति के चश्में से देखना और इसी आधार पर जातिगत भेद खड़ाकर वोट प्राप्त करना यही राजनीतिक कुशलता का उदाहरण बन गया है। महाराष्ट्र की जनता ने इसी विद्वेषपूर्ण मानसिकता को नकारकर सभी के प्रति समान आदर रखने वालों को समर्थन दिया है।

देश में विकास एवं विरासत को समानभाव से स्थापित करने वाले प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ अतिवादी तत्व इंडी गठबंधन के समर्थन में खड़े हुए थे। उनकी यही मानसिकता वोट जिहाद के रूप में प्रकट हुई। महाराष्ट्र में धुले लोकसभा सहित देश की अनेक लोकसभा इसका उदाहरण हैं। धुले लोकसभा में भाजपा उम्मीदवार जहां पांच विधानसभाओं में 1,90,000 मतों से आगे थे, वहीं वोट जिहाद के कारण मुस्लिम प्रभाव वाली मालेगांव सेंट्रल विधानसभा में 1,94,000 मतों से पीछे हुए। सभी क्षेत्रों का समान विकास, केन्द्र एवं राज्य सरकार से सभी सुविधा प्राप्त करने के बाद भी वोट का यह पैटर्न न तो संविधान और न ही लोकतंत्र के लिए उचित है। यह मानसिकता लोकतंत्र को पंगु बनाने का कार्य करेगी। इसी मानसिकता को महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद के विरुद्ध धर्मयुद्ध का नारा दिया था। वोट जिहादी मानसिकता के यही लोग मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा में प्रत्याशी उज्ज्वल निकम को हराने एवं मराठा आरक्षण आन्दोलन में उभरे नेताओं के साथ मिलकर भाजपा को हराने की बात कर रहे थे। अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर महाविकास अघाड़ी से वोटों का सौदा कर रहे थे, जिसमें 2012 जैसे दंगों में शामिल जेलों में बंद गुंडों को छुड़ाने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगें सम्मिलित थीं। वोट जिहाद से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचने वाले ये लोग बांग्लादेश में होने वाले हिन्दू नरसंहार पर चुप रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता का महायुति के पक्ष में वोट उनको प्रत्युत्तर है!

हाथ में संविधान के नाम पर रिक्त पुस्तक लेकर संविधान बचाओं का तथ्यहीन विमर्श खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने किया। भाजपा के आने से संविधान एवं आरक्षण समाप्त होगा, ऐसा भय का वातावरण लगातार बनाने का प्रयास विपक्ष करता रहा। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में उसे आंशिक सफलता भी मिलती दिखाई दी, जो स्वयं चुनी हुई सरकारों को भंग कर संविधान का गला घोंट चुके हों, जिनको बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में लोकतंत्र दिखायी देता हो, जिन्होंने बाबासाहेब आंबेडकर को चुनाव न जीतने दिया हो, जिनकी एकाधिकारवादी मानसिकता से बाबासाहेब को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा हो, जिन्होंने बाबासाहेब को उचित सम्मान न दिया हो, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 54 में से 42 सीटों को महायुति को सौंपकर इस झूठे तथ्यहीन विमर्श को महाराष्ट्र की जनता का सटीक उत्तर है।

स्वयं सत्ता में रहते हुए जिन्होंने मराठा समाज के विकास के लिए कोई नीति न बनायी हो वे भाजपा की सरकार आने पर समाज को विभाजन की राह पर ले जाकर आन्दोलन खड़ा करना एवं परदे के पीछे से उसका समर्थन कर समाज को लड़ाने का प्रयास करें, ऐसी सभी शक्तियों को मराठा समाज के प्रभाव वाली अधिकांश सीटें महायुति को सौंपकर महाराष्ट्र की जनता ने उत्तर देने का कार्य किया है।

देश विघातक यह शक्तियां महाराष्ट्र में विष बीज बोकर समाज में घृणा फ़ैलाने का कार्य लम्बे समय से कर रही थीं। भीमा कोरेगांव के पीछे अर्बन नक्सल जैसे तत्वों की भूमिका सर्वविदित है। सवर्ण-दलित संघर्ष कराना ही इनका उद्देश्य था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम सेवक संघ द्वारा समन्वित सैंकड़ों एनजीओ इस चुनाव में महायुति को हराने का प्रयास कर रहे थे। विदेशी सहायता प्राप्त अनेक समूह एवं व्यक्ति महायुति की पराजय के स्वप्न संजोकर महाराष्ट्र में सक्रिय थे। महायुति की यह विजय सभी के लिए सटीक जवाब है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ महाराष्ट्र के विकास को प्रतिबद्ध ऐसे कसौटी पर कसे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, महायुति का समन्वित प्रयास, सज्जन शक्तियों के सहयोग, भाजपा एवं महायुति के असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये विजय प्राप्त हुई है

जिनके भाषणों में महाराष्ट्र के विकास का कोई चित्र नहीं था, जो नकारात्मकता के आधार पर विष-वमन करके तथ्यहीन भ्रम फैलाकर महाराष्ट्र की विजय के स्वप्न देख रहे थे और अब हारने के बाद सदैव की भांति ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। यह जनादेश उन सभी नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मकता की विजय है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ महाराष्ट्र के विकास को प्रतिबद्ध ऐसे कसौटी पर कसे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, महायुति का समन्वित प्रयास, सज्जन शक्तियों के सहयोग, भाजपा एवं महायुति के असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये विजय प्राप्त हुई है। विकास, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित महाराष्ट्र की सरकार बनाने पर महाराष्ट्र की जनता को कोटिशः धन्यवाद। ■

[लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं]

2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं: नरेन्द्र मोदी

पहले के मुकाबले पांच हजार और नए स्कूल-कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25 प्रतिशत के आस-पास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब-करीब 40 प्रतिशत हो गई है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' की 116वीं कड़ी में 24 नवंबर को कहा कि आज बड़ा ही खास दिन है— आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल-कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है।

आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 'एनसीसी' युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आस-पास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले पांच हजार और नए स्कूल-कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25 प्रतिशत के आस-पास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब-करीब 40 प्रतिशत हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ें।

'विकसित भारत' के निर्माण में युवाओं का बहुत बड़ा रोल

श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश 'युवा दिवस' मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग'। भारत-भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर चुने हुए ऐसे दो हजार युवा भारत मंडपम में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के लिए जुटेंगे।

उन्होंने कहा कि आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है, जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे एक लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' भी ऐसा ही एक प्रयास है।

इतिहास को संजोकर रखने वाले देश का भविष्य भी सुरक्षित रहता है

श्री मोदी ने कहा कि परसों रात ही मैं दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना से लौटा हूं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर गुयाना में भी एक 'मिनी भारत' बसता है। आज से लगभग 180 वर्ष पहले गुयाना में भारत के लोगों को खेतों में मजदूरी के लिए, दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था। आज गुयाना में भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गुयाना का नेतृत्व कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गुयाना की तरह ही दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों की संख्या में भारतीय हैं। दशकों पहले की 200-300 साल पहले की उनके पूर्वजों की अपनी कहानियां हैं। क्या आप ऐसी कहानियों को खोज सकते हैं कि किस तरह भारतीय प्रवासियों ने अलग-अलग देशों में अपनी पहचान बनाई! कैसे उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया! कैसे उन्होंने अपनी भारतीय विरासत को जीवित रखा? मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सच्ची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें।

श्री मोदी ने कहा कि जो देश, जो स्थान अपने इतिहास को संजोकर रखता है, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गांवों के इतिहास को संजोने वाली एक डायरेक्टरी बनाई है। समुद्री यात्रा के भारत के पुरातन सामर्थ्य से जुड़े साक्ष्यों को सहेजने का भी अभियान देश में चल रहा है। इसी कड़ी में लोथल में एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, इसके अलावा आपके संज्ञान में कोई manuscript हो, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो, कोई हस्तलिखित प्रति हो तो उसे भी आप भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद से सहेज सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के 'महापरिनिर्वाण दिवस' पर कार्यक्रम आयोजित

भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 06 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन (एसपीएमआरएफ) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के सामाजिक परिवर्तन में बाबासाहेब के अद्वितीय योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की भी प्रशंसा की गयी, जो भगवान बुद्ध की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद! लाफिंग बुद्धा फिर से मुस्कुरा रहा है। पाली को मान्यता मिलने से दुनिया भर के लोगों, खासकर बौद्ध समुदाय में खुशी की लहर है।"

बाबासाहेब अंबेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा, "डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के भारत के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के लिए सामाजिक न्याय की वकालत की। भारत के लिए उनका महान योगदान 'भारत का संविधान' के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अगले 60 दिनों में भाजपा पूरे देश में घर-घर जाकर लोगों को भारत के संविधान के बारे में जागरूक करेगी।"

कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ ने डॉ. अंबेडकर के प्रति राष्ट्र की शाश्वत कृतज्ञता पर जोर दिया, जिन्होंने भारत में समानता एवं सामाजिक न्याय की नींव रखी। उन्होंने कहा, "सामाजिक परिवर्तन के बारे में डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण राष्ट्र का मार्गदर्शन करता रहेगा। हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में उनका योगदान बेजोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करके और पाली को नयी पहचान देकर इस विरासत को संजोने का काम किया गया है।"

इस अवसर पर प्रख्यात भिक्षुओं, विद्वानों और गणमान्य व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संरक्षित करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने पाली को मान्यता दिए जाने को बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

इस अवसर पर एसपीएमआरएफ के चेयरमैन डॉ. अनिर्बान गांगुली सहित अनेक प्रख्यात भिक्षु उपस्थित थे। ■

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान ने सौ करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा और अगर आपने नहीं किया है, तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देशभर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने सौ करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। सौ करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ पांच महीनों में— ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गुयाना में था, तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली, उनकी पत्नी की माता जी और परिवार के बाकी सदस्य, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही हैं। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाएं, वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इको-सिस्टम विकसित हो। इसलिए ये संस्थाएं कहीं औषधीय पौधे लगा रहीं हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रहीं हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मां, हम सबके लिए जो करती है हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। ■

पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 25 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्ज्वल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की, उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक-एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद; हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें।

श्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदन लोकतंत्र की, 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, देश की जनता को अपने-अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है।

श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता-जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा-अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन-रात मेहनत करें। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

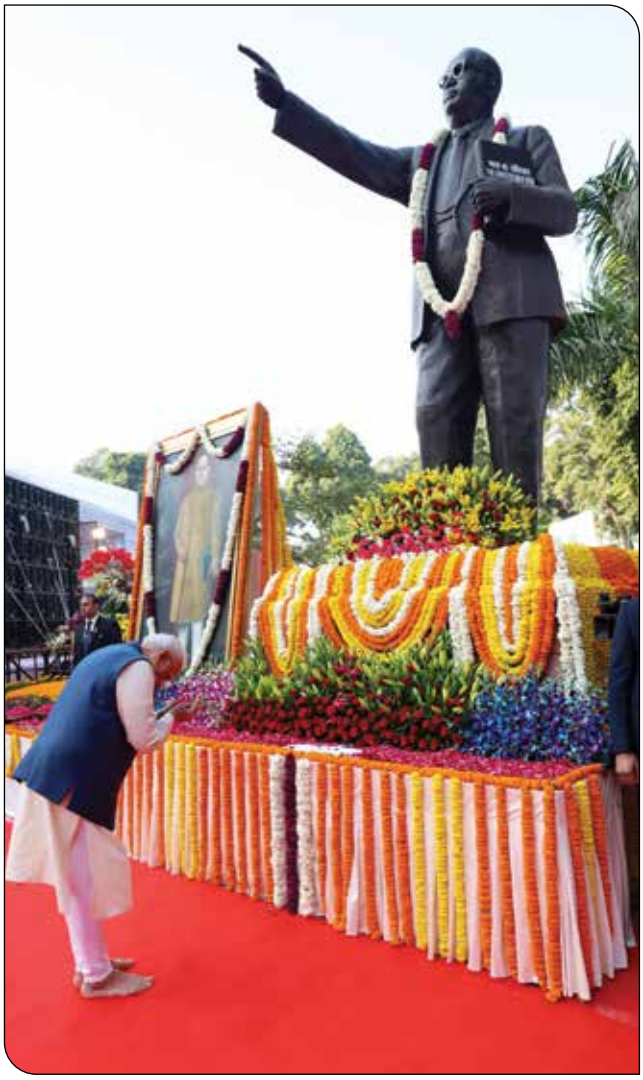

संसद भवन (नई दिल्ली) में 06 दिसंबर, 2024 को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

चंडीगढ़ में 03 दिसंबर, 2024 को नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को दिखाती एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भुवनेश्वर (ओडिशा) में 01 दिसंबर, 2024 को पुलिस महानिदेशकों/ महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 07 दिसंबर, 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस–2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बैज प्रदान करते सैन्य अधिकारी

नई दिल्ली में 05 दिसंबर, 2024 को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 18 दिसंबर, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह